भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2433
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय में वृद्धि

2433. श्री गुरमीत सिंह मीतः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी योजना के परिणामों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो सरकार कब तक ऐसा करने की योजना बना रही है;

(ग) 2019 से अब तक किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में विस्तृत आंकड़े और विश्लेषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से **(घ)**: सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल थीं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोत चिह्नित किए हैं: -

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन की लागत में कमी
iv. फसल गहनता में वृद्धि
v. उच्च मूल्य कृषि की ओर रुख करना
vi. किसानों की उपज के संबंध में लाभकारी मूल्य
vii. अतिरिक्त मैनपावर को कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में शिफ्ट करना

कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 27,662.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,32,469.86 करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है। किसानों के कल्याण के लिए तैयार की गईं भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम, उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करती हैं जिनमें निम्न शामिल हैं:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई)
3. कृषि क्षेत्र हेतु संस्थागत ऋण (इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट)
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. माइक्रो इरिगेशन फ़ंड
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. नमो ड्रोन दीदी
12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना
13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना
14. खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का शुभारंभ
15. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (एआईएफ़)
16. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत
17. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)- क्लस्टर विकास कार्यक्रम
18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम का निर्माण
19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है जिन्होंने अपनी आय दोगुनी से अधिक बढ़ाई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा निश्चित अंतराल पर स्थिति आकलन सर्वेक्षण (सिचुएशन असेस्मेंट सर्वे- एसएएस) किया जाता है। कृषि परिवारों की आय के संबंध में उपलब्ध अंतिम अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2019) के दौरान किए गए कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार, एनएसएस 70वें दौर (वर्ष 2012-13) और एनएसएस 77वें दौर (वर्ष 2018-19) से प्राप्त प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय निम्नानुसार है:

तालिका: वर्ष 2012-13 और 2018-19 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (रुपये) (केवल भुगतान किए गए खर्चों पर विचार करते हुए)

स्तर	कुल आय (रुपये में)	
	70वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2013)	77वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2019)
(1)	(2)	(3)
अखिल भारत	6,426	10,218

******